



NaMo 25 · #25YearsofSeva

44 मंत्रालय · मंत्रालय-दर-मंत्रालय

गृह मंत्रालय

अनुच्छेद 370 से नक्सल-मुक्त भारत तक

7 अक्टूबर 2001 → 7 अक्टूबर 2026 · 25 साल, ज़ीरो ब्रेक · 25YearsofSeva.com · संस्करण 88 · 7 अक्टूबर 2026
हर आँकड़ा तिथि सहित — पूरा रिकॉर्ड वेबसाइट पर।



गृह मंत्रालय अनुच्छेद 370 से नक्सल-मुक्त भारत तक

- 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ; 11 दिसम्बर 2023 को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से इस निर्णय की वैधता पुष्ट की।
- 1 जुलाई 2024 से तीन नई न्याय संहिताएँ लागू हुईं, जिन्होंने 1860 की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह ली।
- 30 मार्च 2026 को लोकसभा में नक्सल-मुक्त भारत की घोषणा हुई: नक्सल-प्रभावित ज़िले अप्रैल 2024 के 38 से घटकर 31 मार्च 2026 को शून्य रह गए।
- पूर्वोत्तर में 2014 से 14 शांति समझौते हुए (नीचे तिथिवार सूची) और 2019 से 10,000 से अधिक कैडर हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे; AFSPA त्रिपुरा और मेघालय से पूरी तरह तथा असम, नागालैंड और मणिपुर के बड़े हिस्सों से हटाया जा चुका है।
- 10 जनवरी 2020 को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) का उद्घाटन हुआ; साइबर-वित्तीय धोखाधड़ी की राष्ट्रीय हेल्पलाइन 2021 में शुरू हुई और फरवरी 2022 से 1930 नंबर पर उपलब्ध है; 19 मई 2025 से ई-ज़ीरो एफआईआर की सुविधा आरम्भ हुई।
- जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी और 1931 के बाद पहली बार इसमें जाति की गणना होगी; ₹11,718 करोड़ की इस गणना का मकान-सूचीकरण चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ।
- वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के चरण-I (2023, ₹4,800 करोड़) और चरण-II (2025, ₹6,839 करोड़) से सीमावर्ती गाँव "अंतिम गाँव" के बजाय "पहले गाँव" के रूप में विकसित हो रहे हैं।